VOLUME-8, ISSUE-8, AUGUST-2019 • PRINT ISSN No. 2277 - 8160

Original Research Paper

Economics

डिजीटल इंडिया : सम्भावनाएँ एवं समस्याएँ

श्रीमती राजरानी खुराना

प्राध्यापक शा.जे.एन.एस. महाविद्यालय, शुजालपुर

KEYWORDS :

परिचय :–

डिजीटल इंडिया भारत सरकार द्वारा आरंभ किया हुआ एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। जिसका मूल उद्देश्य देश के हर विभाग व रिकार्ड को एक ही कड़ी से जोड़ना है। और वह कड़ी है देश की इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम की कड़ी जो कि काम की गति को बढ़ाने में मद्दगार है। डिजीटल इंडिया वह कार्यक्रम है जो कि देश को एक डिजीटल सोसायटी में बदल सकें। और भारत को एक नया रूप दे सकें। डिजीटल इंडिया कार्यक्रम से देश की हर जानकारी और रिकार्ड को स्वच्छता से इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जा रहा है। जो कि आगे काम में सरलता के साथ–साथ तेज रफ्तार भी लाएगा।

डिजीटल इंडिया की शुरूआत :–

डिजीटल इंडिया की शुरूआत दिल्ली के इंदिरा गॉधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा कई बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में हुआ था। डिजीटल इंडिया प्रोजेक्ट मोदी सरकार द्वारा आरंभ किया हुआ एक अहम प्रोजेक्ट है। जो कि देश के हर विभाग को जोड़ता है। इस कार्यक्रम से देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों के सहित 6 लाख गॉव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार ने इस लक्ष्य को 2017 के अन्त तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

डिजीटल इंडिया प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य :–

- *डिजीटल इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की डाटा को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना है जिससे कि देश की संपत्ति को चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी।*
- *वर्तमान में देश में सरकार द्वारा विभिन्न स्कीम चलायी जा रही है। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगो को विभिन्न मद्द प्रदान करना होता है। लेकिन वास्तव में स्कीमों का लाभ सही व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और अयोग्य व्यक्ति ही इसका फायदा ले लेते है।*
- *इस तरह की लोभ और अनैतिक कार्यो को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल पैमेंट और डिजीटल प्रोग्राम का आरंभ किया। डिजीटल पैमेंट का उद्देश्य सही जनता तक उनके हक को पहुँचाना भी है।*
- *इस मुहीम का लक्ष्य देश से कागज कार्यवाही को हटाना है जिससे कि देश की लाखों रूपये खर्च होने के साथ–साथ अनियमिता को भी समाप्त करना है।*
- *गॉव–गॉव में डिजीटल इंडिया के बारे में और डिजीटल इंडिया के महत्व व लाभ के बारे में देश के नागरिकों को बताया। पूरे देश में डिजीटल इंडिया की एक लहर छा जाएगी ताकि देश की तकनीकी सुविधाओं से कोई भी देशवासी वंचित न रहें।*

डिजीटल इंडिया के लाभ :–

डिजीटल इंडिया से हर व्यक्ति की जिंदगी में एक बदलाव आया है। डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से हर व्यक्ति और सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में समय की बचत हो रही है –

- *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से सही जनता को उसका सही लाभ मिल रहा है।*
- *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से रिश्वत की आदत को जड़ से मिटाने मे मद्द मिल रही है।*
- *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से कागजी कार्यवाही में बेकार हो रहे खर्च में कमी होगी।*
- *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से हर चीज की सही सूचना लोगो तक पहुँच रही है।*
- *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से देश में हो रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी पाने में सरलता दिख रही है।*
- *डजीटल इंडिया प्रोग्राम से एक स्वच्छ और सत्य भारत का निर्माण हो रहा है।*
- *डिजीटल इंडिया प्रोजेक्ट एक ऐसी मुहीम है जो कि सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनो को लाभ पहुँचाना है।*
- *वर्तमान समय में देश में विमुद्रीकरण लागू होने के बार से लोगों में डिजीटल इंडिया की काफी ज्यादा आग्रह देखने को मिल रहा है। लोग आजकल अपनी हर खरीद और बिक्री को कैशलेश करना पसंद कर रहे है। छोटे–छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी दुकानों में भी आजकल लगभग हर खरीद–पेटीएम, जैसे कंपनियों के कैशलेश तरीकों से की जा रही है।*
- *सरकार ने नोटबंदी के बाद कैशलेश पैमेंट के तरीको को अपनाने के लिए पूरे देश से अनुरोध किया। देश में कैशलेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एप्प का आरंभ किया गया जो कि लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते। इस एप्प का नाम भीम एप्प रखा गया।*
- *डिजीटल पेमेंट और डिजीटल सुरक्षा का एक माहौल पूरे देश में छाया हुआ है। पे–टीएम, मोबिक्विक जैसी कंपनियों सरकार की डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमोशन में काफी मद्दगार साबित हुए है। आज लगभग पूरा देश इन कंपनियों के डिजीटल पैमेंट के तरीकों को अपनाकर देश की डिजीटल बना रहे है। छोटे से बड़े व्यापारियों को भी ग्राहकों कि सुविधा के लिए इस तरह के पैमेंट और कैशलेश तरीकों को अपनाना पड़ा।*

डिजीटल इंडिया के हानि (समस्याएँ) :–

- *गरीब लोग जिनके पास "Android" मोबाइल ही नहीं है वह "BHIM APP" का लाभ कैसे उठाएगें।*
- *डिजीटल इंडिया से नुकसान गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को होगा क्योकि उन्हे ये तकनीक समझने में और इससे अभियस्त होने में कुछ वक्त लग जाएगा।*
- *इंटरनेट स्पीड :– डिजीटल इंडिया पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित है। ई–भारत का सपना तक ही पूरा होगा जब इंटरनेट की गति तीव्र होगी, लेकिन हम इंटरनेट की गति में बहुत पीछे है। दुनिया में हमारा नम्बर 52 वॉ है। यहॉ डाउनलोड स्पीड 2 एमबीपीएस है।*
- *सुरक्षा पर खतरा :– देश की कम्प्यूटर तथा सूचना प्रणाली इंटरनेट से जुड़ी हुई है। इन पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य है तकनीक के स्वदेशी विकास तथा विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण के बगैर डिजीटल इंडिया का विस्तार विनाशकारी होने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना रहेगा।*
- *बच्चों की इंटरनेट पर सक्रियता :– ई–बैग जैसी सुविधाओं से कम उम्र के बच्चे भी इंटरनेट का प्रयोग करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि डिजीटल इंडिया से बच्चों की इंटरनेट पर सक्रियता बढ़ जाएगी। इससे वे इंटरनेट की अन्य सामग्रियों को भी देखेगें जिसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा। अमेरिका मं 13 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है जबकि एसोचैम के सर्वे के अनुसार भारत में 8 से 13 वर्ष की उम्र के लगभग 73 प्रतिशत बच्चे इंटरनेट पर सक्रिय है।*
- *बिजली की परेशानी :– इंटरनेट पर कार्य करने के लिए बिजली का होना आवश्यक है। स्मार्टफोन की बात छोड़ दी जाए तो गॉवों में तो अभी भी कम्प्यूटर पर इंटरनेट चलाया जाता है। ऐसे में बगैर बिजली के इंटरनेट कैसे चलेगा जबकि गॉवों में आज भी बिजली की 24 घंटे उपलब्धता नही है। आज भी गॉवों में 12 से 20 घंटे बिजली की कटौती होती है। डिजीटल इंडिया के रास्ते में यह सबसे बड़ी परेशानी होगी।*
- *प्रशिक्षण का अभाव :– डिजीटल इंडिया में टेक्नोलॉजी से आम इंसान का काम तो आसान बनेगा, लेकिन उन्ही का जिन्हे इंटरनेट का पूर्ण ज्ञान हो। अब अगर गॉव में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो आज भी इंटरनेट प्रशिक्षण में पीछे है। ऐसे से जालसाजी और धोखाधड़ी का भी डर बना रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले तकनीक का पूरा ज्ञान देना होगा, उसके बाद ही भारत को डिजीटल बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।*
- *ई–कॉमर्स कंपनियों का वर्चस्व :– देश में ई–कॉमर्स का मौजूदा बाजार करीब 13 अरब डॉलर का है। इस व्यापारिक मॉडल में न्यूनतम रोजगार के नकारात्मक पहलू के अलावा देश का पैसा ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विदेश जा रहा है। इन कंपनियों द्वारा करोड़ो की टैक्स चोरी भी की जाती है।*

डिजीटल इंडिया की 9 चुनौतियॉ :–

Nice Pillars Of Digital India

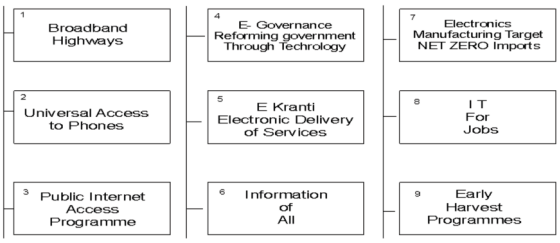

सरकार का पहला लक्ष्य है ब्रॉडबैड हाइवे। इसके तहत देश के आखिरी घर तक ब्रॉडबैड के जरिए इंटरनेट पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का प्रोग्राम जो तीन चार साल पीछे चल रहा है। सरकार को समझना होगा कि जब आप गॉव–गॉव तार बिछाने जाएगें तो आप उन लोगों को ये काम नहीं सौप सकते जो पिछले 50 साल से कुछ और बिछा रहे है।

सरकार का दूसरा लक्ष्य है सबके पास फोन की उपलब्धता जिसके लिए जरूरी है कि लोगो के पास फोन खरीदने की क्षमता हो। सोच अच्छी है लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि क्या सबके पास फोन खरीदने की क्षमता आ गयी है। या फिर सरकार अगर ये सोच रही है कि खुद सस्ते फोन बनाएगी तो इसके लिए तकनीक और तैयारी कहॉ है?

तीसरा स्तम्भ है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हर किसी के लिए इंटरनेट हो यह अच्छी बात है इसके लिए पीसीओ के तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाए जा सकते है ये पीसीओ आसानी से समस्या हल कर सकते है। लेकिन हर पंचायत के स्तर पर इसको लगाना और चलाना कोई आसान काम नहीं है इसी के चलते पिछले कई साल से योजना लंबित है।

चौथा स्तम्भ हैं ई–गवर्नेंस यानी सरकारी दफ्तरों को डिजीटल बनाना और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का इसे लागू करने का पिछला अनुभव बताता है कि दफ्तर डिजीटल होने के बाद भी उनमें काम करने वाले लोग डिजीटल नही हो पा रहे है।

पॉचवा स्तम्भ है ई–क्रांती ये ई–गवर्नेंस से जुड़ा मामला है और सरकार की इच्छा है कि इंटरनेट के जरिए गॉव–गॉव तक पहुँचे। ई–क्रांति के लिए हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा प्रशिक्षण और उपकरण सबकुछ डिजीटल होना जरूरी है।

सरकार ने अपने लिए छटवा लक्ष्य रखा है इंफोर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को जानकारियॉ उपलब्ध करायी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि एक्सेस टू इंफोर्मेशन के अभाव में यह कैसे संभव है ? इसके लिए जरूरी है अच्छा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर होना ताकि लोग आसानी से जानकारियॉ पा सकें। साथ ही इसके तहत सिर्फ सूचनाएँ पहुँचाना सरकार का लक्ष्य है या जमीनी सूचनाएँ इक्ठ्ठी करना भी है। अगर सिर्फ पहुँचाना मकसद है तो यह गैर लोकतांत्रिक है।

सातवॉ लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का इसके तहत उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कलपुर्जो के आयात को शून्य करना है। यह कभी भी संभव नहीं है क्योकि पूरी दुनिया चाहती है व्यापार करना।

जहॉ तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन का सवाल है तो अभी तक हम इस मामले में शहरों तक ही सीमित है और गॉवों तक जा ही नही रहे है। इसमें नीति और नियमितता की चुनौतियॉ बहुत ज्यादा है।

डिजीटल क्रांती के लिए नौवा स्तम्भ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इसका संबंध दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाजिरी से है।

डिजीटल इंडिया की सफलता :–

डिजीटल इंडिया भारतीयों की जिंदगी में वह परिवर्तन लाने का मिशन है जिससे की हर उपभोक्ता को अपने रोजमर्रा जीवन की कई काम पहले से आसान और कम खर्च में निभाने का मौका दे रही है।

डिजीटल इंडिया की कई सफल कहानियॉ हैं –

1) *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से देश के हर गॉव को डिजीटल गॉव का रूप मिला :– अब सरकार डिजीटल इंडिया से देश के हर गॉव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। यह काम करीब 1 साल पहले से शुरू किया जा चुका है इसके लिए देश के हर एक गॉव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह काम देश की टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल को सौंपा जा चुका है।*
2) *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से कार्य विधि में तेजी और सटीकता की एक पहल बन गयी :– डिजीटल इंडिया के जाद् से देश की आर्थिक शहर मुम्बई के सभी कोर्ट और कार्यालयों से टाइपराइटर के इस्तेमाल को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। देश की कार्य व्यवस्था को और तेज रफ्तार देने के लिए ये नया कदम उठाया जाएगा।*
3) *डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से गाड़ियों की आर.सी. करवाने में अब आसानी :–*

अब देश में गाड़ियों की आर.सी. बनाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नही है। क्योकि डिजीटल इंडिया के कारण अब आर.सी. बस कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन बन जायेगी जिससे समय बचत हुई। ये देशवासियों के लिए एक वरदान है।

निष्कर्ष :–

तकनीक हमेशा से नवयुग में प्रवेश का माध्यम रही है। चाहे वह पेपर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, ब्लैकबोर्ड हो, पुस्तके हो अथवा इक्सीसवीं सदी का मोबाईल, ब्रॉडबैड और इंटरनेट सुविधा हो। अब देखना यह होगा कि इस नव–क्रांती का हम कितना सकारात्मक उपयोग करते है। पर उतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे–जैसे ग्रामीण भारत, सूचनातंत्र से जुड़ता जाएगा और एक बार पुनः हम वैश्विक स्तर पर अपना ज्ञान पताका फहरा पायेगें।

संदर्भ ग्रंथ :–

डिजीटल इंडिया *(अजय कुमार)*
दैनिक भास्कर *(नवम्बर 2019)*
नईदुनिया *(2019)*

Digital India :
Government Transportation
(Vitasta publication PVT. Ltd.)

डिजीटल इंडिया और भारत *(विराग गुप्ता)*

Digital India : A Soio
Eonomic Transformation
(Dr. Rajeev Sijariya & Rahul Sharma)
Bharti Publiaticns